स्वच्छ भारत से होगा समग्र भारत का विकास

–सिद्धार्थ झा

व्यापक परिदृश्य में देखें तो 'स्वच्छ भारत' का सपना हमारी उन छोटी-छोटी आदतों पर टिका है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। सिर्फ नदी-नाले, सड़क या भवनों की साफ-सफाई तक इस सपने को सीमित न करें बल्कि दो कदम आगे बढ़ते हुए ये सोचे कि हम इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान दे सकते हैं। हम और आप एक जागरूक नागरिक की तरह सिर्फ सोचे ही नहीं, व्यवहार भी करें। क्योंकि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, सक्षम और मजबूत भारत देने का ख्वाब हम सभी का है।

सन 2019 में भारत जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहा होगा तब तक भारत में एक बहुत बड़े सपने का लक्ष्य साकार कर लिया गया होगा। एक ऐसा सपना जिसे देखने के लिए हमें आजादी के बाद भी 67 साल लग गए लेकिन इसको हकीकत बनने से अब कोई रोक नही सकता। 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से इस महाक्रान्ति का आह्वान किया तब लोगों को अहसास हुआ कि ऐसा कुछ है जो वो जाने–अनजाने में भूल जाते हैं। हम लोग घर–दफ्तर तो साफ रखते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में गली–मोहल्लों में क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं।

गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का। गांधी जी का नजरिया इसको लेकर काफी रचनात्मक और क्रांतिकारी था। ये ऐसा काम था जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में जोड़ता था। चाहे सामूहिक उपवास हो या फिर चरखा चलाना या फिर साफ–सफाई, स्वच्छता–ये ऐसे काम थे जहां ऊंच–नीच या भेदभाव का कोई स्थान नहीं था ,सब लोग मिल–जुल कर काम किया करते थे। ये बताने की जरूरत नहीं कि महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा महत्व रखती थी। वो भारत को 'स्वच्छ' भारत के रूप में देखना चाहते थे। ग्रामीण भारत की दयनीय दशा से पूरी तरह से वाकिफ थे। लेकिन बहुत दुखद है कि आज भी देश की बड़ी आबादी खुले में शौच के लिए विवश है। तकनीक के सहारे हम हर हाथ में मोबाइल देने में तो कामयाब हो गए लेकिन हर घर में एक शौचालय दे सकें इसमें हमारे नीति–निर्माता असफल रहे। सोचिए, एक तरफ हम आर्थिक और तकनीकी रूप से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहे। दूसरी तरह हमारे अपने ही भाई–बहन सिर पर मैला ढोने का अमानवीय काम करते रहे। सोचिए, कितना शर्मनाक धब्बा साबित होता होगा इस मुल्क के लिए जब दुनिया हमारे बारे में ये सब पढ़ती–सुनती होगी। सवा अरब की आबादी वाले देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं।

वर्ष 2012 की विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि स्वच्छता के अभाव में हम हर साल लगभग 54 अरब डॉलर गंवा देते हैं दवाई, इलाज या फिर बीमारी में कामकाज पर न जाने के कारण। यानी हर भारतीय औसतन 6500 रुपये गंवा देता है। इन विपरीत परिस्थितियों में पहली बार लोगों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर अहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नही है बल्कि ये हमारा काम है। प्रधानमंत्री का भाषण उन लाखों सफाई कर्मचारियों की आवाज बनकर उभरा जिसको देखकर लोग हिकारत से मुंह मोड़ लिया करते थे और ये समझते थे कि ये काम तुच्छ है और वही लोग करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू उठाया तो साफ–सफाई के मायने बदल गए। बड़े–बड़े नौकरशाह, मंत्री, बाबू, अभिनेता, खिलाडी और पत्रकार भी झाड़ू लेकर उस अभियान में कूद गए जिसे पूरा करने पर हम गांधीजी के सपनों का भारत बना सकें। 'स्वच्छ भारत' अभियान को लेकर अभी तक काफी कुछ लिखा–पढ़ा जा चुका है कि कैसे इस अभियान को जन–जन का आंदोलन बनाने की कवायद की गई है। बकायदा सभी देशवासियों से प्रधानमंत्री ने सालभर में 100 घंटे के श्रमदान की अपील भी की जिसका काफी असर पड़ा। इस अभियान का लक्ष्य खुले में शौच को रोकना, हर घर मे शौचालय का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और कचरे का सही तरीके से निपटान करना है। इसके अलावा इस अभियान का मुख्य मकसद लोगों में सफाई के प्रति जागरुकता लाना भी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा मे दिए अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि स्वच्छता जन अभियान बनने की दिशा मे अग्रसर है और इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि आजादी के दशकों बाद कम से कम संसद में इस मुद्दे पर बहस तो हुई है।

'स्वच्छ भारत' अभियान एक व्यापक अभियान है जिसको पूरा करने के लिए चौतरफा रणनीति बनाई गई है जिससे कि लक्ष्य को हासिल करने में कोई कठिनाई ना हो। स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 18 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया जो देशभर में स्वच्छता और साफ पानी देने के लिए बेहतर और आधुनिक तरीकों पर अपने सुझाव देगी। ये समिति ऐसी संभावनाओं और हल की खोज करेगी जो व्यावहारिक हो और जिन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके।

'स्वच्छ भारत' अभियान को दो हिस्सों मे बांटा गया है–स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत अभियान शहरी। इन दोनों के लिए पेयजल और स्वच्छता की जिम्मेदारी क्रमश ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गांव को योजना की तारीख से अगले पांच साल तक 20 लाख रुपये की धनराशि मुहैया करवाएगा। इस अभियान के तहत सरकार हर परिवार को व्यक्तिगत रूप से 12 हजार रुपये की धनराशि शौचालय के निर्माण के लिए दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस अभियान पर 134000 करोड़ रुपये की धनराशि का खर्च आएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों मे एक करोड़ से ज्यादा घरों को इसमें शामिल किया गया है जिसके लिए बजटीय आवंटन 62 हजार करोड़ रु रखा गया है। जहां पर घरेलू शौचालय बनाने में दिक्कत होगी वहां सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही, ठोस कचरे के निपटान के लिए भी काम किया जा रहा है। आम स्थानों जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इस पूरी योजना में अनुमानतः 1 लाख 86 हजार करोड़ रु. खर्च आएगा जिससे देशभर मे 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां शुष्क शौचालय यानी बायो टॉयलेट्स के निर्माण पर काम जारी है। इस अभियान में दो प्रमुख चुनौतियों पर काम किया जा रहा है । पहला ग्रामीण भारत में साफ–सफाई की कमी एक महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु है दूसरी चनौती लोगों की सोच को बदलना है। हम कब सड़कों पर कचरा न फेंकना खुद सीखेंगे। लोग खुद कब अपने इलाके को साफ–सुथरा रखना सीखेंगे। ये दोनों काम अगर हो जाते हैं तो शायद कभी भी इस तरह के अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये अभियान अब तक कहां पहुंचा है।

अगस्त 2015 में सरकार की तरफ से कहा गया कि 'स्वच्छ भारत' अभियान की शुरुआत के बाद से शौचालयों के निर्माण में 446 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में 46 प्रतिशत घरो में अपने शौचालय हैं। 2 महीने के बाद 'स्वच्छ भारत' अभियान में शुरू हुए लगभग 2 साल का समय हो जाएगा लेकिन चरणबद्ध तरीके से समय से काफी पहले ही हम इस योजना में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। आज शौचालय निर्माण का काम काफी तेजी से हो रहा है। दलगत राजनीति से कोसों दूर हर राज्य सरकार, पार्टी, विभिन्न विचारधाराओं के

लोगों के समर्थन से आज ये व्यापक रूप धारण कर चुका है। पूरी दुनिया आशान्वित नजरों से हमारी ओर देख रही है कि हम कैसे इतनी बड़ी समस्या से इतने बड़े मुल्क को निजात दिलाते हैं क्योंकि तभी उन देशों के लिए भी सम्भावनाओं की राहें खुलेंगी।

उनके 15 अगस्त, 2014 को ही दिए हुए भाषण का केंद्रबिंदु हमें उनकी बेटियों के प्रति चिंता भाव में झलकता है जिसमें उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया। गांव–देहात ही नहीं शहरों में भी ऐसे बहुत से विद्यालय मिल जाते थे जहा पर शौचालय नहीं थे। उन्हें आसपास खेत या झाड़ियों में जाना पड़ता था। इससे न सिर्फ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों होती हैं बल्कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध का शिकार भी होना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से लडकियों का ड्रापआउट रेट स्कूलों में कहीं ज्यादा था। इस छोटी–सी मगर महत्वपूर्ण सुविधा के अभाव में जाने कितनी ही कल्पना चावला, किरण बेदी सरीखी प्रतिभाओं ने अकाल ही दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' की घोषणा करते हुए एक वर्ष के भीतर देश भर में 13 करोड़ 70 लाख लड़कें एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय निर्माण करने का वादा किया था। ऐसे 2,62,000 स्कूल चिन्हित किए गए जहां 4,24,000 शौचालयों का निर्माण होना था। आज देश भर में अब लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं।

'बाल स्वच्छता' इस 'स्वच्छ भारत अभियान' का प्रमुख हिस्सा है। क्योंकि 'स्वच्छ आदर्श भारत' बनाने में ये नई पौध भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली है। ये बच्चे स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो दूसरो को उनके स्कूल, घरों, आसपास के वातावरण को साफ रखने में जागरुकता फैला रहे हैं। सही मायनों में मैं इन्हें 'स्वच्छता के राजदूत' के तौर पर देखता हूं और समाज में इनकी वजह से बहुत बदलाव आया है। दरअसल इन बच्चों पर भरोसे का श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है जब इन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 125 वे जन्मदिवस पर बाल स्वच्छता अभियान की नींव डाली थी जो 14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक चलाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर साल 2014 मे ही गांधी जयंती से विद्यालयों में स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया। इसके अंतर्गत बच्चों में वो छोटी–छोटी मगर महत्वपूर्ण आदतों को अपनाने को प्रेरित किया गया जो उन्हें निरोगी बनाए रखें मसलन खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, साफ वर्दी, कटे नाखून, रुमाल रखना, विद्यालय परिसर को साफ रखना। आज ये सभी अच्छी आदतें उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। वास्तविकता में ये अभियान आज भी बच्चों के मन–मस्तिष्क और उनके क्रियाकलापों में जारी है। बाल स्वच्छता अभियान भी स्वस्थ भारत अभियान का एक अहम् हिस्सा है।

विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुमान के मुताबिक हर साल 50 लाख से ज्यादा मौतों की वजह सिर्फ मानव मल से होने वाली बीमारियां हैं और इसमें भी बड़ी संख्या है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की। ये आंकड़े यहीं खत्म नहीं होते ये सिर्फ शुरुआत है। स्थिति इससे कहीं अधिक भयावह है। आंकड़े बताते हैं हर साल विश्वभर में 20 लाख बच्चे डायरिया, 6 लाख बच्चे गंदगीजनित रोगों और 55 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैजे की चपेट मे आकर मरते हैं। इसमें भी आबाधी संख्या हमारे यानी भारतीय बच्चों की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मे रोजाना पांच साल से कम उम्र के एक हजार बच्चों की मौत अस्वच्छता से जुड़ी बीमारियों मसलन डायरिया, हेपेटाइटिस और हैजे जैसे रोगों से होती हैं।

बाल स्वच्छता अभियान की जरूरत इसलिए भी है अगर बच्चे छोटी उम्र में इन बीमारियों का शिकार नहीं भी हुए तो भी अस्वच्छता की वजह से होने वाले रोग इनको घेर लेते हैं जो इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर असर डालता है। स्वास्थ्य संबंधी शोध बताते हैं कि कुपोषण सिर्फ पौष्टिक आहार की कमी से नहीं बल्कि अस्वच्छता की वजह से भी होता है जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। ये ज्यादातर गंदे हाथों से खाना खाने की वजह से होता है जिसके लिए पिछले दो साल में अनेक जागरुकता अभियान और प्रचार माध्यम का सहारा लिया गया। आज बच्चे गांव–गांव, घर–घर में स्वच्छता के दूत बने हुए हैं जो प्रधानमंत्री का संदेश जन–जन तक पहुंचा रहे हैं और स्वच्छ भारत की हकीकत को बहुत हद तक पाने में मदद भी कर रहे है। बाल स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जितनी सक्रियता दिखाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है क्योंकि उसकी प्रभावी नीतियों का ही नतीजा है कि आज सरकारी स्कूलों में साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल छात्रों को सुलभ है।

स्वच्छ भारत की दिशा में सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं जन–जन का बरसों पुराना एक और सपना है कि भारत की जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा निर्मल अविरल बहती रहे। लेकिन गंगा–यमुना की सफाई के नाम पर अब तक गाया तो बहुत गया, साथ ही पैसा भी बहुत बहाया गया लेकिन गंगा दिन–प्रतिदिन मरती रही। स्वयंसेवी संस्थाओं, लालफीताशाही और राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण गंगा नदी से जीवन चक्र ही समाप्ति की दिशा में है। केंद्र सरकार की गंगा नदी को साफ करने की मुहिम का नाम है 'नमामि गंगे' परियोजना जिसे

2037 करोड़ रु. की आरंभिक राशि के साथ शुरू किया गया जिसका बजट बढ़ाते हुए अगले 5 साल में ये राशि 20 हजार करोड़ रु कर दी गई है। भारत के पांच राज्य उत्तराखंड, झारखण्ड, बिहार,उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल गंगा नदी के पथ पर आते हैं। इस योजना के तहत गंगा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियो की भी सफाई की जाएगी। क्योंकि पिछले कई दशकों से अनुपचारित गंदगी और औद्योगिक अपशिष्ट डालने की वजह से गंगा की स्थिति बद से बदतर हुई है। इन राज्यों के 118 शहरो से गंगा नदी का प्रवाह है। इसकी साफ–सफाई और रखरखाव के लिए इससे सम्बंधित मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकाय के अलावा गांव के सरपंचों तक की मदद हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया है क्योंकि जन–भागीदारी और जागरुकता ही गंगा को स्वच्छ करने का कारगर औजार साबित होंगे।

हाल ही में जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 'नमामी गंगे' उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसकी स्वच्छता और लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत झारखंड से की जा चुकी है। इस अभियान को पूरा करने के लिए गंगा टास्क फोर्स, गंगा के तटों पर वनीकरण, गंगा की सफाई के लिए सवा सौ टीमें गठित की हैं। इसके साथ ही तकनीकी अध्ययन तक कराने में कोई कसर नही छोड़ी गई है। इतना ही नहीं कई देशों के साथ तकनीकी के समझौते भी किए गए हैं जिससे इस योजना का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकार का पूरा ध्यान गंगा नदी पर प्रवाह उपचार संयंत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना से गन्दगी को साफ करने का है। सिर्फ इतना ही नहीं गंगा चूंकि हमारी आस्थाओं का केंद्रबिंदु है इसलिए सिर्फ वैज्ञानिक या पर्यावरणविद् ही नहीं देशभर के साधू–संतों को इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। इसी का नतीजा है उज्जैन में अभी सिंहस्थ कुम्भ चल रहा है। पूरे विश्व की नजरें इस पर लगी हुई हैं। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में जो नजारा हाल ही में अभी धार्मिक नगरी में देखने को मिला जब तमाम धर्म गुरुओं ने एक स्वर में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए इस अभियान को व्यापक समर्थन दिया और एक मंच पर खड़े होकर शौचालय बनाने पर बल देते हुए स्वच्छता क्रांति लाने का आह्वान किया। विभिन्न धर्म गुरुओं ने सद्भावना संकल्प के जरिए स्वच्छता क्रान्ति लाने का आह्वान किया और देश के नागरिकों से अपील की वे इस कार्य मे जुट जाएं ताकि भारत की स्वच्छता वैश्विक उदाहरण बन सके।

'स्वच्छ भारत' अभियान भारतीय रेल के प्रयासों के उल्लेख के बिना अधूरा है। जिस तरह से भारतीय रेलों में पहले से बेहतर साफ–सफाई का प्रबंध हुआ है, इसके लिए देशभर में उसके भागीरथी प्रयासों की सराहना हुई है। रेल की पटरियों में जाने कितना मलमूत्र रोज बिना उपचार के गिरता है जिसकी वजह से रेल की पटरी के किनारे रहने वालों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस समस्या के निदान के लिए सभी ट्रेन मे बायो टॉयलेट लगाने की शुरुआत हो रही है और जिस गति से काम चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल सौ प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में स्टेशन पर जिस तरह की साफ–सफाई का नजारा देखने को मिलता है निसंदेह इसके पीछे भी 'स्वच्छ भारत' का मंत्र काम कर रहा है। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं यात्री भी जागरूक हुए हैं अपने कर्त्तव्यों को लेकर। रेलवे की संवेदनशीलता का इससे बेहतरीन नमूना क्या हो सकता है कि अब रेलमंत्री को किए हुए हर ट्वीट पर तुरंत कार्यवाही होती है। ऐसे तमाम स्टेशन तो एकबारगी साफ–सफाई के मामले में एयरपोर्ट सरीखा एहसास करवाते हैं– रायपुर, नई दिल्ली,हैदराबाद, भोपाल ऐसे तमाम स्टेशन की लिस्ट में मौजूद हैं।

व्यापक परिदृश्य में देखें तो 'स्वच्छ भारत' का सपना हमारी उन छोटी–छोटी आदतों पर टिका है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। सिर्फ नदी–नाले, सड़क या भवनों की साफ–सफाई तक इस सपने को सीमित न करें बल्कि दो कदम आगे बढ़ते हुए ये सोचे कि हम इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान दे सकते हैं। आज उपभोक्तावादी युग में हम यूज एंड थ्रो संस्कृति का हिस्सा हैं। क्या कभी आपने मिनरल वाटर की बोतल,प्लास्टिक के चाय का कप ,कलम, चिप्स, पैकेट और तमाम उन मशीनों के बारे में सोचा है जिनका बेहद कम इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं। किसी भी सरकार, किसी भी देश के लिए। इस तमाम कचरे को निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जगह–जगह कचरे के पहाड़ हिमालय से भी ऊंचे होते जा रहे हैं इनका समाधान क्या है। कैसे हम अपनी जरूरतों को सीमित करके हिन्दुस्तान को कूड़ास्तान बनने से रोकें।

इस दिशा में अब समय आ गया है कि हम और आप एक जागरूक नागरिक की तरह सिर्फ सोचे ही नहीं व्यवहार भी करें। क्योंकि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, सक्षम और मजबूत भारत देने का ख्वाब हम सभी का है। उम्मीद है साल 2019 में गांधी जयंती के दिन जब भारत में सुबह की पहली किरणें जगमगाएंगी तब पूरे विश्व में इसकी रोशनी ये संदेश देगी कि गांधी जी आज भी जीवित हैं उन सभी सपनों में जो उन्होंने कभी भारत भूमि के लिए देखे थे कभी जात–पात, अस्पृश्यता की समाप्ति पर तो कभी 'स्वच्छ भारत' के हकीकत बनने पर।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं तथा लोकसभा टीवी में कसंल्टेंट हैं।)
ई–मेलः jha.air.sidharath@gmail.com